बंद कताई मिलों की जमीन पर उद्योग खुलेंगे

■ **NBT रिपोर्ट, लखनऊ :** सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड कानपुर की बंद पड़ी कताई मिलों की 451.20 एकड़ भूमि यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट अथॉरिटी (UPSIDA) को दी जाएगी, जिससे इस पर नए उद्योग स्थापित हो सकें। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। हस्तांतरित भूमि में सीतापुर के महमूदाबाद की 71.02 एकड़, फतेहपुर की 55.31 एकड़, प्रयागराज की मऊआइमा की 85.24 एकड़, गाजीपुर के बहादुरगंज की 78.92 एकड़, फर्रुखाबाद की कंपिल की 82.15 एकड़ और बुलंदशहर की 78.56 एकड़ जमीन शामिल है। ये इकाइयां दो दशकों से बंद पड़ी हैं। सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।

गोरखपुर सहित 7 शहरों में स्मार्ट सिटी योजना का विस्तार

यूपी में 17 स्मार्ट सिटी विकसित की जा रही हैं। इसमें 10 का चयन केंद्र सरकार ने किया था जबकि 7 का विकास राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत हो रहा है। इसमें गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, शाहजहांपुर और गोरखपुर शामिल हैं। इन सातों नगर निगमों में राज्य स्मार्ट सिटी योजना का दो साल के लिए विस्तार करने का फैसला किया गया है।

लखनऊ नोड में विकसित होगा डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर

डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम (DTIS) विकसित की जाएगी। इसके जरिए नोड में कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर स्थापित होगा। इसका उपयोग यहां स्थापित रक्षा इकाइयों अपने उत्पादों के परीक्षण एवं सर्टिफिकेशन के लिए करेंगी। कैबिनेट ने इसके लिए 0.8 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है।

मेडिकल कॉलेजों के लिए जमीन, बजट की किल्लत दूर

कैबिनेट ने अलग-अलग जिलों में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, अस्पतालों के विस्तार के लिए जमीन व बजट की किल्लत दूर कर दी है। बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए कारागार विभाग की 14.05 एकड़ जमीन चिकित्सा शिक्षा विभाग को दी जाएगी। इसमें 12.39 एकड़ भूमि पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी व कॉलेज परिसर में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की मूर्ति स्थापित होगी। वहीं, बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए राजकीय कृषि विद्यालय के नाम दर्ज 4570 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क दी जाएगी। इससे नर्सिंग कॉलेज के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। वहीं, इटावा के सैफई में स्थित पीजीआई में 300 बेड ऑब्स ऐंड गायनी ब्लॉक के निर्माण के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इसमें 100 बेड का पीडियाट्रिक ब्लॉक भी शामिल है। कैबिनेट ने 232.17 करोड़ रुपये की संशोधित लागत को मंजूरी दे दी है।

ये फैसले भी हुए

- बजट सत्र के सत्रावसान को मंजूरी
- आगरा मेट्रो के प्रथम कॉरिडोर के लिए उद्यान विभाग की 8684.68 वर्ग मीटर भूमि एवं दूसरे फेज के लिए गृह विभाग की 20,753 वर्ग मीटर भूमि मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को 1 रुपये के प्रतीक शुल्क पर लीज पर दी जाएगी
- हरदोई में महर्षि दधीचि कुंड के विकास के लिए 0.850 हेक्टेयर जमीन पर्यटन विभाग को मुफ्त दी जाएगी
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में कार्यरत सात कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा

किसानों से 4300 रुपये वर्गमीटर जमीन खरीदेगा यीडा

यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट अथारिटी (YEIDA) किसानों से जेवर एयरपोर्ट के दूसरे फेज के लिए 4300 रुपये वर्गमीटर की दर से जमीन खरीदेगा। कैबिनेट ने 40% से अधिक बढ़ोतरी के प्रस्ताव को सहमति दे दी है। यीडा अभी 3,100 रुपये वर्गमीटर जमीन अधिग्रहीत कर रहा था। इसको लेकर किसान सहमत नहीं थे और जमीन का दाम बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सीएम ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल से लखनऊ में मुलाकात की थी। इस दौरान ही उन्होंने उनकी मांग पूरी करने का आश्वासन दिया था। कैबिनेट की बैठक में इसे अमली जामा पहना दिया गया है। 243 हेक्टेयर से अधिक जमीन अधिग्रहीत की जानी है।